

प्रेषक,

मनीषा पंवार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

आयुक्त,  
ग्राम्य विकास,  
उत्तराखण्ड पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

विषय:- मुख्यमंत्री युवा स्वावलम्बन योजना प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में। देहरादून दिनांक: 04 जनवरी, 2017

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कृषि, उद्यान, पुष्प उत्पादन, जड़ी-बूटी उत्पादन, रेशम उत्पादन (Agriculture, Horticulture, floriculture, Herbiculture, and Sericulture) तथा तत्संबंधी क्षेत्रों में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं के समूहों को स्व रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वावलम्बन योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त योजना की विशेषताएं/घटक निम्नानुसार हैं:-

1. मुख्यमंत्री युवा स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत इच्छुक शिक्षित बेरोजगार युवाओं की सूची वरिष्ठता के आधार पर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, ग्राम्य विकास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. उपलब्ध सूची के आधार पर ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम पांच तथा मैदानी क्षेत्रों में कम से कम दस युवाओं को एक स्वयं सहायता समूह में संगठित किया जायेगा। समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या 15 होगी। इन समूहों को आधुनिक तकनीक हस्तांतरण करते हुये सशक्त किया जायेगा। स्वयं सहायता समूह के गठन एवं संचालन संबंधी प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जायेगा।
3. तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन (यू0के0एस0डी0एम0) के माध्यम से युवाओं के गठित समूहों को संबंधित क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।
4. संबंधित विभाग (कृषि, उद्यान, वन, जड़ी-बूटी तथा रेशम आदि) द्वारा इन स्वयं सहायता समूहों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर संबंधित योजनाओं से तकनीकी, वित्तीय आदि समस्त अनुमन्य लाभ दिये जायेंगे।
5. राज्य की भूमि लीज नीति के तहत संबंधित स्वयं सहायता समूह द्वारा नियमानुसार स्वयं लीज पर भूमि की व्यवस्था की जायेगी।
6. समाज कल्याण विभाग द्वारा नियमानुसार अनु0जाति/अनु0जनजाति के समूहों/समूह से जुड़े युवाओं को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से समस्त अनुमन्य लाभ शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर दिये जायेंगे।
7. नाबार्ड द्वारा इस योजना में गठित समूहों को सशक्त करने हेतु नाबार्ड सहायतित योजनाओं से वित्तीय/तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा।
8. अन्य बैंकों के साथ-साथ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा भी विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषण उपलब्ध कराया जायेगा।
9. राज्य की भूमि लीज नीति के तहत समूह द्वारा लीज पर ली गई भूमि में यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न हो तो जलागम विभाग द्वारा उक्त परिक्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी।
10. समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन के लिये पैकेजिंग, ब्रांडिंग आदि में तकनीकी सहयोग आइफैड द्वारा सहायतित समेकित आजीविका सुधार परियोजना (आई0एल0एस0पी0) द्वारा किया जायेगा।

11. योजना के सफल एवं सुचारु संचालन हेतु समस्त रेखीय विभाग इस हेतु उत्तरदायी होंगे। इस योजना का अनुश्रवण मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें अन्य संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य होंगे। उक्त समिति के अनुमोदनोपरांत एस0पी0एम0यू0 ग्राम्य विकास विभाग द्वारा समय-समय पर परामर्शिका/मार्ग निर्देश जारी किये जायेंगे।
12. राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई ग्राम्य विकास विभाग द्वारा विभिन्न विभागों से इन समूहों के सशक्तिकरण हेतु विशेष परियोजनाये भी तैयार करने का प्रयास किया जायेगा।
13. विभिन्न रेखीय विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं के वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग के साथ-साथ ग्राम्य विकास विभाग द्वारा इस योजना के तहत गठित युवा स्वयं सहायता समूहों को निम्नानुसार वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी—
  - 13.1 समूह गठन के उपरांत बैंक खाता खोलने पर रू0 25000/— प्रति समूह सीड कैपिटल के रूप में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी जो कि समूह की परिकामी निधि(रिवाल्विंग फंड) होगी।
  - 13.2 समूह का माइक्रोक्रेडिट प्लान बैंक द्वारा स्वीकृत होने पर रू0 1,25,000/— प्रति समूह की दर से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में समूह के खाते में डी0बी0टी0 के तहत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त धनराशि बैंक द्वारा स्वीकृत कुल माइक्रो क्रेडिट प्लान की लागत का भाग होगा।
  - 13.3 नोडल विभाग द्वारा वर्ष में कुल स्वीकृत योजना लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत धनराशि का उपयोग प्रशासकीय कार्यों, योजना के व्यापक प्रचार प्रसार, कार्यशाला के आयोजन तथा अनुश्रवण आदि पर व्यय किया जायेगा।
3. उक्तानुसार योजना प्रारम्भ किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है। वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी आदेश वित्त विभाग की सहमति से पृथक से जारी किये जायेंगे।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या 20 / XI / 16 / 56(82)2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी को मा0मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, ग्राम्य विकास मंत्री जी को मा0मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रभारी सचिव, गोपन को उनके अशासकीय पत्र संख्या 4/2/1/XXI/2017-सी0एक्स0, दिनांक 03.01.2017 के क्रम में सूचनार्थ।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व/कृषि/सिंचाई/जलागम/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/वन/श्रम एवं सेवायोजन/तकनीकी शिक्षा/उद्यान/समाज कल्याण/सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0, विकास भवन, सर्वेचौक, देहरादून।
9. मुख्य परियोजना निदेशक, आई0एल0एस0पी0, पंडितवाड़ी, देहरादून।
10. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. मुख्य/महा प्रबन्धक, नाबार्ड, राजपुर रोड, देहरादून।
12. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
(युगल किशोर पन्त)  
अपर सचिव।